**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 769**
**29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

# सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंग संबंधी भविष्यवाणी

**769. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंग संबंधी भविष्यवाणी को बढ़ावा देने वाले वीडियो डालने को विनियमित करने के लिए कोई कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ग): सरकार सोशल मीडिया मंचों पर लिंग संबंधी भविष्यवाणी को बढ़ावा देने वाले वीडियो की पोस्टिंग को 'गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994' के अंतर्गत विनियमित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है -

- पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 22 में लिंग निर्धारण/चयन को बढ़ावा देने वाले किसी भी विज्ञापन, जिसमें डिजिटल प्लेटफार्म पर डाले गए विज्ञापन भी शामिल हैं, को निषिद्ध किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।

- मंत्रालय में एक नोडल एजेंसी का गठन किया गया है जो शिकायतें प्राप्त करने और पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 22 के उल्लंघनों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए एकल संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करती है।

- पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 22 के उल्लंघन के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विभिन्न सर्च इंजनों द्वारा नियमित रूप से संस्थानिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है।

- विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और रेडियो पर नोडल एजेंसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें जनता से पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 22 के तहत किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट नोडल एजेंसी को देने का आह्वान किया गया है ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

*********